web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

Social Justice Union — Govt. Registered

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 19 सितंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 352

वन नेशन-वन इलेक्शन को मिली मंजूरी, मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास

नई दिल्ली । आरएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस पहल के जरिए भारत में चुनावों की प्रक्रिया को सरल और समेकित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत हो सकेगी।

कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया था। शाह ने कहा था कि एक देश एक चुनाव सरकार इसी कार्यकाल में लागू करेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में भी एक देश एक चुनाव के वादे को शामिल किया था। यह कदम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, और इसके संभावित प्रभावों पर देश भर में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

बता दें, वन नेशन-वन इलेक्शन की दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने 191 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इन विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जा सकें।

32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, 15 ने विरोध किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को स्वीकार की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार 'एक देश, एक चुनाव'' पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था जिनमें से 47 ने जवाब दिया. इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया.

अपनी "एक देश, एक चुनाव" योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंद्रह राजनीतिक दलों ने कोई जवाब नहीं दिया.

राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने प्रस्ताव का विरोध किया जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने इसका समर्थन किया.

रिपोर्ट में कहा गया है, ''47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई. पंद्रह राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 राजनीतिक दलों ने न केवल एक साथ चुनाव की प्रणाली का समर्थन किया, बल्कि सीमित संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपनाने की वकालत भी की.''

इसमें कहा गया है, ''एक साथ चुनाव का विरोध करने वालों ने आशंका जताई थी कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है, यह लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है, इससे क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला जा सकता है और राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा मिल सकता है.''

मार्च में समिति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, 'आप', कांग्रेस और माकपा ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है. बसपा ने इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के संबंध में चिंताओं को उजागर किया, जिससे इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

समाजवादी पार्टी (सपा) ने कहा कि यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो जहां तक चुनावी रणनीति और खर्च का सवाल है तो राज्य स्तरीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे इन दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ जाएगा.

इन पार्टियों ने किया विरोध- राज्य की पार्टियों में एआईयूडीएफ, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, भाकपा, द्रमुक, नगा पीपुल्स फ्रंट और सपा ने प्रस्ताव का विरोध किया.

इन पार्टियों ने किया समर्थन- अन्नाद्रमुक, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल (सोनेलाल), असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी (आर), मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

इन पार्टियों ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया- भारत राष्ट्र समिति, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल (सेक्युलर), झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

महत्वपूर्ण एवं खास

राजौरी में सेना का वाहन खाई में गिरने से एक जवान शहीद

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना का एक वाहन खाई में गिर जाने से एक जवान शहीद हो गया और पांच अन्य घायल हो गए है। जानकारी के अनुसार जवानों को ले जा रहा सेना का वाहन एक गहरी खाई में गिर गया जिससे छह जवान घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां एक जवान का निधन हो गया। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सभी रैंक लांस नायक बलजीत सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जो मंजाकोट, राजौरी के पास आतंकवाद विरोधी ड्यूटी के दौरान एक दुखद सडक़ दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर थे।'

भिंड में बड़ा हादसा : आश्रम की दीवार गिरने से साधू समेत 3 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम

भिंड (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बड़ा हादसा हो गया. जहां एक आश्रम की दीवार गिरने से 1 साधू और 3 गौवंशों की मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची. फिलहाल, टीम राहत कार्य में जुट गई है. बता दें कि जिले में पिछले करीब 14 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. गांव-शहर की गलियां जल मग्न हो गए हैं. लगातार बारिश होने से कई जगह से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है. इधर, अटेर में नावली वृंदावन के जंगल में स्थित पागल बाबा आश्रम की दीवार गिर गई. दीवार की चपेट में आने से संत छविराम दास और 3 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. टीम संत और गौवंश के शवों को बाहर निकालने के कार्य में जुट गई है.

नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले- सडक़े बहुत बना ली, अब खराब काम करने वालों को हटाना है

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के रखरखाव को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दुहाई इंटरचेंज पर आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सी सडक़ें बना दी हैं, लेकिन अब खराब काम करने वालों को सिस्टम से बाहर करना जरूरी है। गडकरी ने कहा, हमारे सडक़ के काम में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ लोगों को मेरे हाथों से रिटायर होना चाहिए। कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कुछ की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। मैंने आज देखा कि सडक़ का रखरखाव बहुत गंदा था। उन्होंने आगे कहा कि जो एजेंसियां अच्छे कार्य करेंगी, उन्हें हर साल पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि गंदा काम करने वालों को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। गडकरी ने कहा, हम टॉयलेट्स की भी जांच करेंगे। जो अच्छा काम नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी कंपनी हो, उसे भी ब्लैकलिस्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि वह और उनके राज्यमंत्री अब सडक़ों की जांच करेंगे और खराब काम करने वालों को बाहर करेंगे। उन्होंने कहा, अब हमें लोगों को रिटायर करना, सस्पेंड करना और ब्लैकलिस्ट करने का काम करना है। मेरी बात को गंभीरता से लें। मैंने अपने राजमंत्रियों से कहा है कि वे हर सडक़ पर जाएं, और मैं भी उनका साथ दूंगा। जो अच्छा काम करेगा, उसे सम्मान मिलेगा और जो बुरा करेगा, उसे सिस्टम से बाहर किया जाएगा।

ईरान में बस हादसे में 10 लोगों की मौत, 36 घायल

तेहरान। ईरान के यज्द प्रांत में एक बस के पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 36 अन्य लोग घायल हो गए। ईरान के यातायात पुलिस प्रमुख हसन मोमेनी ने बताया कि यह घटना मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार, प्रात: 2.20 बजे अर्दकान काउंटी में साघांद गांव के पास हुई। यह घटना बस के मुख्य सडक़ से भटककर एक माइनिंग एक्सेस मार्ग पर चले जाने के बाद पलटने की वजह से हुई। मोमेनी ने कहा कि बस दक्षिणी ईरानी प्रांत बुशहर से उत्तर पूर्वी शहर मशहद जा रही थी। तभी यह हादसा हुआ। घायलों को यज़्द के चिकित्सा केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सुनीता विलियम्स दूसरी बार अंतरिक्ष में ही मनाएंगी बर्थडे, अभी लौटने में लग सकते हैं और 4-5 महीने

नई दिल्ली । आरएनएस

सुनीता विलियम्स 'महिला एक, व्यक्तित्व अनेक' की सच्ची कहानी है। इस समय स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण वह पिछले आठ महीने से स्पेस में फंसी हुई हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें धरती पर लौटने में अभी चार-पांच महीने और लग सकते हैं।

अपने साथियों के साथ तमाम चुनौतियों का डटकर सामना कर रहीं भारतीय मूल की यह अंतरिक्ष यात्री 19 सितंबर को धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर अपना 59वां जन्मदिन मानएंगी। इससे पहले भी वह स्पेस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हैं।

सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था। वह भारत के गुजरात (अहमदाबाद) से ताल्लुक रखती हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। उनसे पहले कल्पना चावला के नाम यह उपलब्धि रही थी।

जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई हैं। वह सितंबर/अक्तूबर 2007 में भारत भी आई थीं। जून, 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग-अलग विमानों में 3,000 हजार घंटे से ज्यादा उड़ान भरी है। साथ ही सुनीता सोसायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, सोसायटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स और अमेरिकी हेलिकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं।

हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान

फरीदाबाद । आरएनएस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में भाजपा की चुनावी रैली में दावा किया कि सेना से लौटे हर अग्निवीर को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है और बचे हुए सभी अग्निवीरों को हरियाणा में रोजगार दिया जाएगा। रैली में फरीदाबाद जिले की सभी छह विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भी उपस्थित थे।

गृह मंत्री ने हरियाणा की पहचान को जवानों, किसानों और खिलाडिय़ों के साथ जोड़ते हुए कहा, हरियाणा देश का गौरव है। यहां के किसान देश की जनता का पेट भरते हैं और यहां के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह झूठ फैला रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया कि कांग्रेस ने सैनिकों की धरती हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं लागू की।

अमित शाह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की, जिसमें केजीपी, केएमपी और जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए हैं।

इसके अलावा, शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके उम्मीदवारों की जनसभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह विदेश जाकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं और कश्मीर में आतंकियों को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने विश्वास जताया कि भाजपा सरकार के रहते कश्मीर से हटाई गई धारा 370 को फिर से लागू नहीं होने दिया जाएगा।

चंद्रयान-4 मिशन को भी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली । आरएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को भी पृथ्वी पर लाने की योजना है, ताकि उनका अध्ययन किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने शुक्र ग्रह की कक्षा संबंधी अभियान, गगनयान, और चंद्रयान-4 अभियान के विस्तार को भी मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एक अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को भी स्वीकृति दी है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन का पेलोड स्थापित कर सकेगा।

चंद्रयान-4 मिशन के लिए 2,104.06 करोड़ रुपये के फंड की आवश्यकता होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह मिशन 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, जिसमें डॉकिंग/अनडॉकिंग, लैंडिंग, और नमूना संग्रह शामिल हैं। इसरो इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी निभाएगा, और उम्मीद जताई गई है कि उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से यह मिशन 36 महीनों के भीतर पूरा होगा।

इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जो कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

भारत ने पाकिस्तान सरकार के सामने रखी शर्त, कहा- 'सिंधु जल संधि में अब संशोधन की जरूरत

नई दिल्ली । आरएनएस

सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने कहा है कि वह सिंधु जल संधि के पुराने समझौते पर अब बदलाव चाहता है।

भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद ङ्गढ्ढढ्ढ (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू-कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

भारत के इस कदम के पीछे विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के साथ विवाद किया है। उसने भारत के कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया है। पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल संधि में उनके हितों की अनदेखी की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों को लगता है कि वे सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

वहीं, पाकिस्तान ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बदलाव के खिलाफ होगा क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता है।

अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में खाली करेंगे सरकारी मकान, जल्द ही तय किया जाएगा नया ठिकाना

नई दिल्ली । आरएनएस

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी सुविधाएं छोडऩे का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बताया कि केजरीवाल एक हफ्ते में सरकारी आवास खाली कर देंगे।

संजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को कई सुविधाएं मिली हुई थीं, उन्होंने इस्तीफा देने के तुरंत बाद सभी सरकारी सुविधाएं छोडऩे का निर्णय लिया। जबकि अन्य नेता सरकारी सुविधाओं से चिपके रहते हैं, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आवास खाली करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि उन पर हमले भी हुए हैं। सिंह ने कहा, यह घर आवश्यक है, लेकिन केजरीवाल का मानना है कि उनकी रक्षा ईश्वर करेंगे। उन्होंने छह महीने जेल में भी बिताए हैं।

संजय सिंह ने यह भी कहा कि अभी यह तय नहीं है कि केजरीवाल कहां रहेंगे, लेकिन जल्द ही कोई ठिकाना निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने पिछले दो सालों से केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की है। झूठे मुकदमे लगाए गए और उन्हें भ्रष्टाचार का आरोपी बताया गया। कोई अन्य नेता ऐसा होता तो इस्तीफा नहीं देता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं।

संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता दुखी और गुस्से में है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल नहीं होते, तो दिल्ली का क्या होता? मुफ्त शिक्षा और इलाज कौन देगा? लोगों को इस पर सोचना होगा।

21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में नामित सीएम आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एलजी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मुर्मू को भेज दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह दिल्ली में रैलियों का आयोजन करेगी जिनमें अरविंद केजरीवाल जनता का फीडबैक लेंगे। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण की तिथि 21 सितंबर प्रस्तावित की है। यही नहीं एलजी ने निवर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र भी राष्ट्रपति मुर्मू को भेज दिया है। हालांकि,ॅ्क्क विधायक दल की ओर से अभी तक मनोनीत सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई तिथि प्रस्तावित नहीं की गई है। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को केजरीवाल ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यही नहीं आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि आतिशी को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में आतिशी के सुरक्षा घेरे पर फैसला लिया जाएगा। मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के सीएम को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। दिल्ली पुलिस इस श्रेणी के तहत पालियों में लगभग 22 जवानों को तैनात करती है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल की सुरक्षा की भी समीक्षा करेगी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा मिली है। इसके तहत केजरीवाल को एक पाली में करीब 40 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाते हैं।